भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2558

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025

सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

केरल में कौशल विकास और उद्यमिता योजनाएं

2558. श्री शफी परम्बिल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केरल राज्य में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही कौशल विकास और उद्यमिता योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है और वडकरा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कितने प्रशिक्षण केंद्र हैं; और

(ग) क्या सरकार का उक्त निर्वाचन क्षेत्र में युवा उद्यमिता प्रशिक्षण के उद्देश्य से नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से, केरल राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल,

पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करना है।

एमएसडीई की कौशल विकास योजनाएँ मांग आधारित हैं और देश भर में ज़रूरत के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते हैं या लगाए जाते हैं। देश भर में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत स्थापित या लगाए गए प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ केरल और वडकारा निर्वाचन क्षेत्र (केरल के कन्नूर और कोझिकोड जिले) का विवरण इस प्रकार है:

	पीएमकेवीवाई केंद्र	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस प्रतिष्ठान	आईटीआई	
				राजकीय	निजी
अखिल भारत	14,844	289	49,788	3,316	11,296
केरल	145	09	1,904	149	297
कन्नूर जिला	04	-	233	11	23
कोजिकोड़े जिला	12	-	192	16	29

इसके अलावा, एमएसडीई ने अपने स्वायत्त संस्थानों, यानी राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (नीसबड), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से केरल राज्य सहित पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। केरल राज्य सहित पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई द्वारा की गई कुछ पहलों का विवरण:

(i) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) - एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों (नीसबड और आईआईई) के माध्यम से पीएम जनमन के कौशल और उद्यमशीलता घटक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना को लागू कर रहा है। नीसबड ने वर्ष 2024-25 के दौरान केरल राज्य में 425 प्रतिभागियों सहित देश भर में 37,642 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण आयोजित किया है।

(ii) जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल - नीसबड ने अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 तक जेएसएस में टीओटी और ईडीपी कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए एक परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता-निर्माण, सलाह और मार्गदर्शन के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना का

निर्माण, पोषण और संवर्धन करना है। नीसबड ने 2,633 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें केरल राज्य में वर्ष 2022-23 के दौरान 69 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है।

(iii) नीसबड ने औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) योजना के अंतर्गत अक्तूबर 2023 से मई 2024 के बीच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन गतिविधियों के बाद उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) से गुजरने के लिए संभावित उद्यमियों का चयन, प्रशिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की गई। नीसबड ने देश भर में 77,430 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है।

(iv) उचित मूल्य की दुकान मालिकों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम - नीसबड ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है नीसबड ने देश भर में 315 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है।

(v) उचित मूल्य की दुकान मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम - नीसबड ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सहयोग से उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यह परियोजना एफपीएस स्वामित्व को उद्यमशीलता के विभिन्न पहलुओं, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता और सरकारी सहायता इकोसिस्टम के गहन ज्ञान से लैस करके उन्हें अपना व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाती है। नीसबड ने देश भर में 315 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है।

(vi) औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) योजना के तहत आईआईई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के एनएसटीआई और आईटीआई में उद्यमशीलता विकास प्रकोष्ठों की स्थापना की है। आईआईई ने उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित किए हैं, जिसके बाद मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की गई इसके अलावा, 94 आईटीआई और 2 एनएसटीआई के 80 संकायों ने एफडीपी के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

*****